International Journal of Research in Social Sciences
Vol. 9 Issue 4, April 2019,
ISSN: 2249-2496 Impact Factor: 7.081
Journal Homepage: http://www.ijmra.us, Email: editorijmie@gmail.com
Double-Blind Peer Reviewed Refereed Open Access International Journal - Included in the International Serial Directories Indexed & Listed at: Ulrich's Periodicals Directory ©, U.S.A., Open J-Gate as well as in Cabell's Directories of Publishing Opportunities, U.S.A

प्रमुख सरकारों और राजनीतिक संगठनों में वीटो शक्तियों का अध्ययन

डॉ महेंद्र कुमार मीणा
राजनीति वज्ञान वभाग
श्री गो वंद गुरु राजकीय महा वद्यालय बांसवाड़ा राज

सार

वीटो एक आधिकारिक कार्रवाई को एकतरफा रूप से रोकने की कानूनी शक्ति है। सबसे विशिष्ट मामले में, एक राष्ट्रपति या सम्राट किसी विधेयक को कानून बनने से रोकने के लिए वीटो करता है । कई देशों में, देश के संविधान में वीटो शक्तियाँ स्थापित हैं । वीटो शक्तियाँ सरकार के अन्य स्तरो पर भी पाई जाती हैं, जैसे राज्य, प्रांतीय या स्थानीय सरकार और अंतर्राष्ट्रीय निकायों में।

कुछ वीटो पर काबू पाया जा सकता है, अक्सर एक सर्वोच्च बहुमत वोट सेरू संयुक्त राज्य अमेरिका में, सदन और सीनेट का दो–तिहाई वोट राष्ट्रपति के वीटो को ओवरराइड कर सकता है। हालांकि, कुछ वीटो पूर्ण हैं और इन्हें ओवरराइड नहीं किया जा सकता है। उदाहरण के लिए, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में, स्थायी सदस्यों (चीन , फ्रांस , रूस , यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका) के पास सुरक्षा परिषद के किसी भी प्रस्ताव पर पूर्ण वीटो है ।

कई मामलों में, वीटो शक्ति का उपयोग केवल यथास्थिति में परिवर्तन को रोकने के लिए किया जा सकता है। लेकिन कुछ वीटो शक्तियों में बदलाव करने या प्रस्तावित करने की क्षमता भी शामिल है। उदाहरण के लिए, भारतीय राष्ट्रपति वीटो वाले बिलों में संशोधन का प्रस्ताव करने के लिए संशोधनात्मक वीटो का उपयोग कर सकते हैं।

अधिकांश आधुनिक वीटो का उद्देश्य सरकार की शक्ति, या सरकार की एक शाखा , आमतौर पर विधायी शाखा की जाँच के रूप में होता है। इस प्रकार, शक्तियों के पृथक्करण वाली सरकारों में , वीटो को सरकार की उस शाखा द्वारा वर्गीकृत किया जा सकता है जो उन्हें अधिनियमित करती है

परिचय

एक संशोधनात्मक वीटो या संशोधनात्मक अवलोकन प्रस्तावित संशोधनों के साथ विधायिका को कानून लौटाता है, जिसे विधायिका या तो अपना सकती है या ओवरराइड कर सकती है। विधायी निष्क्रियता का प्रभाव अलग–अलग हो सकता हैरू कुछ प्रणालियों में, यदि विधायिका कुछ नहीं करती है, तो वीटो वाला बिल विफल हो जाता है, जबकि अन्य में, वीटो वाला बिल कानून बन जाता है।

International Journal of Research in Social Sciences
Vol. 9 Issue 4, April 2019,
ISSN: 2249-2496 Impact Factor: 7.081
Journal Homepage: http://www.ijmra.us, Email: editorijmie@gmail.com
Double-Blind Peer Reviewed Refereed Open Access International Journal - Included in the International Serial Directories Indexed & Listed at: Ulrich's Periodicals Directory ©, U.S.A., Open J-Gate as well as in Cabell's Directories of Publishing Opportunities, U.S.A

क्योंकि संशोधनात्मक वीटो कार्यपालिका को विधायी प्रक्रिया में एक मजबूत भूमिका देता है, इसे अक्सर एक विशेष रूप से मजबूत वीटो शक्ति के मार्कर के रूप में देखा जाता है।

राष्ट्रपति और अर्ध–राष्ट्रपति प्रणालियों में, वीटो राष्ट्रपति पद की एक विधायी शक्ति है, क्योंकि इसमें कानून बनाने की प्रक्रिया में राष्ट्रपति शामिल होता है। सक्रिय शक्तियों के विपरीत जैसे कानून पेश करने की क्षमता , वीटो एक प्रतिक्रियाशील शक्ति है, क्योंकि राष्ट्रपति किसी विधेयक को तब तक वीटो नहीं कर सकता जब तक कि विधायिका इसे पारित नहीं कर देती।

कार्यकारी वीटो शक्तियों को अक्सर तुलनात्मक रूप से ष्मजबूतष या ष्कमजोरष के रूप में स्थान दिया जाता है। एक वीटो शक्ति को उसके दायरे के आधार पर मजबूत या कमजोर माना जा सकता है, इसे प्रयोग करने की समय सीमा और इसे ओवरराइड करने के लिए वीटो निकाय की आवश्यकताएं। सामान्य तौर पर, ओवरराइड के लिए जितने अधिक बहुमत की आवश्यकता होती है, वीटो उतना ही मजबूत होता है।

पैकेज वीटो की तुलना में आंशिक वीटो ओवरराइड के लिए कम असुरक्षित हैं और इस मामले का अध्ययन करने वाले राजनीतिक वैज्ञानिकों ने आम तौर पर कार्यपालिका को पैकेज वीटो की तुलना में अधिक शक्ति देने के लिए आंशिक वीटो माना है। हालांकि, अमेरिकी राज्य सरकार में लाइन–आइटम वीटो के अनुभवजन्य अध्ययन ने अपने एजेंडे को आगे बढ़ाने की कार्यपालिका की क्षमता पर कोई सुसंगत प्रभाव नहीं पाया है। हटाने योग्य वीटो की तुलना में संशोधित वीटो कार्यपालिका को अधिक शक्ति प्रदान करते हैं, क्योंकि वे कार्यपालिका को नीति को अपने पसंदीदा राज्य के करीब ले जाने की शक्ति देते हैं, अन्यथा यह संभव नहीं होता।लेकिन यहां तक कि एक स्थगन पैकेज वीटो जिसे एक साधारण बहुमत द्वारा ओवरराइड किया जा सकता है, कानून को रोकने या संशोधित करने में प्रभावी हो सकता है।

भारतीय राष्ट्रपति की निलंबनकारी वीटो शक्ति के बारे में तथ्य नीचे दिए गए हैं – राष्ट्रपति अपने निलंबनकारी वीटो का उपयोग तब करता है जब वह विधेयक को पुनर्विचार के लिए भारतीय संसद को लौटाता है। – भारतीय संसद द्वारा विधेयक के पुनरू पारित होने से उसके निलंबनकारी वीटो को खत्म किया जा सकता है। यदि संसद भारतीय राष्ट्रपति को संशोधन के साथ या बिना संशोधन के विधेयक को दोबारा भेजती है, तो उसे अपनी वीटो शक्तियों का उपयोग किए बिना विधेयक को मंजूरी देनी होगी। – राज्य विधेयकों के संबंध में, राज्य विधायिका के पास राष्ट्रपति के निलंबित वीटो को ओवरराइड करने की कोई शक्ति नहीं है। राज्यपाल राष्ट्रपति के विचार के लिए विधेयक को रोक सकता है और भले ही राज्य विधायिका विधेयक को राज्यपाल और राज्यपाल को राष्ट्रपति के

International Journal of Research in Social Sciences
Vol. 9 Issue 4, April 2019,
ISSN: 2249-2496 Impact Factor: 7.081
Journal Homepage: http://www.ijmra.us, Email: editorijmie@gmail.com
Double-Blind Peer Reviewed Refereed Open Access International Journal - Included in the International Serial Directories Indexed & Listed at: Ulrich's Periodicals Directory ©, U.S.A., Open J-Gate as well as in Cabell's Directories of Publishing Opportunities, U.S.A

पास भेजती है, फिर भी वह अपनी सहमति रोक सकता है। – जब संसद विधेयक को राष्ट्रपति के पास दोबारा भेजती है, तो उसे सदनों में केवल सामान्य बहुमत का पालन करना होता है, उच्च बहुमत का नहीं। – धन विधेयक के संबंध में राष्ट्रपति अपने निलंबनकारी वीटो का प्रयोग नहीं कर सकता है।

भारतीय राष्ट्रपति की पॉकेट वीटो शक्ति के बारे में तथ्य नीचे दिए गए हैं

बिल को राष्ट्रपति द्वारा अनिश्चित काल के लिए लंबित रखा जाता है जब वह अपने पॉकेट वीटो का प्रयोग करता है। वह न तो विधेयक को अस्वीकार करता है और न ही विधेयक को पुनर्विचार के लिए लौटाता है। – संविधान राष्ट्रपति को कोई समय–सीमा नहीं देता है जिसके भीतर उन्हें विधेयक पर कार्रवाई करनी होती है। इसलिए, राष्ट्रपति अपने पॉकेट वीटो का उपयोग तब करता है जब उसे बिल पर कार्रवाई नहीं करनी होती है। – अमेरिकी राष्ट्रपति के विपरीत, जिसे 10 दिनों के भीतर विधेयक को फिर से भेजना होता है, भारतीय राष्ट्रपति के पास ऐसा कोई समय–नियम नहीं होता है।

आधुनिक समय में विशेष रूप से संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना और नवीन राज्यों के उदय के बाद राष्ट्रों के आपसी संबंधों का मामला और भी अधिक महत्वपूर्ण हो गया है। परिणामस्वरूप प्रत्येक राज्य को अन्य राज्यो की सरकारों की दृष्टि से एक विशेष रीति से व्यवहार करना पड़ता है। साधारण शब्दों में कहा जाये तो उस व्यवहार का अध्ययन ही विषय की सामग्री है। प्रत्येक राज्य का व्यवहार किसी न किसी रूप में हर दूसरे राज्य के व्यवहार पर प्रभाव डालता है, चाहे वह अनुकूल प्रभाव हो या प्रतिकूल तथा अन्य राज्य राज्यों के प्रतिकूल प्रभाव को न्यूनतम करने और अनुकूल प्रभाव को अधिकतम करने का प्रयास करता है।

स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् अपने भाषण में नेहरू ने बहुत सहीं ढंग से इस बात को उजागर किया है कि ''अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम हम पर बरबस प्रभाव डालता है।'' हम इसकी उपेक्षा नहीं कर सकते हैं, अतः विदेश नीति की सही परिभाषा इस प्रकार से की जा सकती है कि विदेश नीति निर्धारित आंतरिक नीतियों के सफल क्रियान्वयन के लिए कुशलता पूर्वक अंतर्राष्ट्रीय वातावरण को अपने अनुकूल बनाने की बात करती है।

प्रमुख सरकारों और राजनीतिक संगठनों में वीटो शक्तियों का अध्ययन

जब संसद में कोई विधेयक पेश किया जाता है, तो संसद विधेयक को पारित कर सकती है और विधेयक के अधिनियम बनने से पहले इसे भारतीय राष्ट्रपति के अनुमोदन के लिए प्रस्तुत किया जाना होता है। यह भारत के राष्ट्रपति पर निर्भर करता है कि वे या तो विधेयक को अस्वीकार करते हैं,

International Journal of Research in Social Sciences
Vol. 9 Issue 4, April 2019,
ISSN: 2249-2496 Impact Factor: 7.081
Journal Homepage: http://www.ijmra.us, Email: editorijmie@gmail.com
Double-Blind Peer Reviewed Refereed Open Access International Journal - Included in the International Serial Directories Indexed & Listed at: Ulrich's Periodicals Directory ©, U.S.A., Open J-Gate as well as in Cabell's Directories of Publishing Opportunities, U.S.A

विधेयक को लौटाते हैं या विधेयक पर अपनी सहमति वापस लेते हैं। विधेयक पर राष्ट्रपति की पसंद को उसकी वीटो शक्ति कहा जाता है। भारत के राष्ट्रपति की वीटो पावर भारतीय संविधान के अनुच्छेद 111 द्वारा निर्देशित है।

भारतीय राष्ट्रपति की पूर्ण वीटो शक्ति के बारे में तथ्य नीचे दिए गए हैं – जब राष्ट्रपति अपने पूर्ण वीटो का प्रयोग करता है, तो एक विधेयक कभी भी अस्तित्व में नहीं आता है। बिल भारतीय संसद द्वारा पारित होने के बाद भी समाप्त हो जाता है और अधिनियम नहीं बनता है। –राष्ट्रपति निम्नलिखित दो मामलों में अपने पूर्ण वीटो का उपयोग करता है (प) जब संसद द्वारा पारित विधेयक एक निजी सदस्य विधेयक होता है (पप) जब राष्ट्रपति विधेयक पर अपनी सहमति देने से पहले कैबिनेट इस्तीफा दे देता है। नई कैबिनेट राष्ट्रपति को सलाह दे सकती है कि वह पुराने कैबिनेट द्वारा पारित विधेयक को अपनी सहमति न दें। नोटरू भारत में, राष्ट्रपति ने पहले अपने पूर्ण वीटो का प्रयोग किया है। 1954 में इसका प्रयोग राष्ट्रपति के रूप में डॉ. राजेंद्र प्रसाद ने किया था और बाद में 1991 में इसका इस्तेमाल तत्कालीन राष्ट्रपति आर वेंकटरमन ने किया था।

जार्ज माडेल्स्की ने विदेश नीति की परिभाषा इस प्रकार से किया है कि, ''विदेश नीति उन क्रियाकलापों का समुच्चय है जिसे किसी समुदाय ने अन्य राज्यों का व्यवहार बदलने के लिए और अपने क्रियाकलाप को अंतर्राष्ट्रीय परिस्थिति के साथ समायाजित करने के लिए विकसित किया है।'' उनकी दृष्टि में विदेश नीति का सबसे पहला कार्य यह होना चाहिए कि वह उन तरीकों पर प्रकाश डाले जिनसे राज्य अन्य राज्यों का व्यवहार बदलने का यत्न करते हैं और उसे बदलने में सफल भी होते हैं। अतः माडेल्स्की की इस परिभाषा के विश्लषण से यही अर्थ निकलता है कि विदेशी नीति का उद्देश्य भविष्य में ऐसी अवस्था पैदा करना है जो स्पष्टतः निर्धारित उन व्यवहार प्रतिरूपों को इंगित करते हैं, जो राष्ट्रीय गतिविधि, हितों, उद्देश्यों एवं नीतियों के मार्गदर्शक होते हैं और हरेक सिद्धांत किसी खास रीति से कार्य करने का एक प्रकार का आदेश होता है। इसका कारण यह है कि प्रत्येक समुदाय ऐसे कार्यों को स्वतः करने योग्य मानता है।

1964 में चीन के परमाणु शक्ति बन जाने के बाद से ही भारत अमेरिकी संबंधों में परमाणु समस्या ने प्रमुख स्थान ले लिया। अमेरिका को शक था कि भारत भी चीन का अनुसरण करते हुए अपना बम तैयार कर लेगा जिससे परमाणु शस्त्रों के प्रसार में और वृद्धि होगी। अमेरिका ने अन्य कई देशों के साथ मिलकर परमाणु प्रसार की रोकथाम की दिशा में प्रयास शुरू कर दिए जिनके फलस्वरूप 1968 में परमाणु अप्रसार संधि पर हस्ताक्षर किए गए। भारत ने इसमें शामिल होने से यह कहते हुए इनकार कर दिया कि इस संधि में उन देशों के साथ भेदभाव किया गया है जो परमाणु हथियारों से संपन्न नहीं हैं। इसमें अन्य देशों को तो परमाणु शक्ति बनने से रोका गया है परंतु पाँच परमाणु शक्ति

International Journal of Research in Social Sciences
Vol. 9 Issue 4, April 2019,
ISSN: 2249-2496 Impact Factor: 7.081
Journal Homepage: http://www.ijmra.us, Email: editorijmie@gmail.com
Double-Blind Peer Reviewed Refereed Open Access International Journal - Included in the International Serial Directories Indexed & Listed at: Ulrich's Periodicals Directory ©, U.S.A., Open J-Gate as well as in Cabell's Directories of Publishing Opportunities, U.S.A

संपन्न देशों – अमेरिका, सोवियत संघ, फ्रांस, इंगलैंड और चीन – को परमाणु प्रसार की छूट दी गई है। इस भेदभावपूर्ण संधि को नकारते हुए भारत ने 1974 में शांतिपूर्ण परमाणु विस्फोट (पी.एन.ई) कर दिया। इससे भारत और अमेरिका के रिश्तों में एक बार फिर राजनीतिक खटास आ गई क्योंकि यह विस्फोट 1971 के युद्ध में भारत की विजय के लगभग 3 वर्ष बाद तथा हिंद–चीन से अमेरिकी फौजों की वापसी के कारण अमेरिका की स्थिति दुर्बल हो जाने के दौरान किया गया था।

शांति बनाए रखने के लिए जिम्मेदार विश्व निकाय के अन्य सदस्यों द्वारा वांछित कार्रवाई को अवरुद्ध करने का एक राष्ट्र का अधिकार अब दो तरफ से आग के अधीन है। छोटे राज्य संयुक्त राष्ट्र चार्टर द्वारा सुरक्षा परिषद के पांच स्थायी सदस्यों को दी गई सामान्य वीटो शक्ति को चुनौती दे रहे हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका और संयुक्त राष्ट्र परमाणु ऊर्जा आयोग में प्रतिनिधित्व करने वाले अधिकांश अन्य बड़े और छोटे राज्य इस बात पर जोर दे रहे हैं कि वीटो सिद्धांत के पास परमाणु शक्ति के विनाशकारी उपयोगों से सुरक्षा के लिए अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था में कोई स्थान नहीं हो सकता है।

सर्वोच्च महत्व से कम के मामलो पर सुरक्षा परिषद में रूस द्वारा अपने वीटो के अधिकार के लगातार प्रयोग ने परिषद के मतदान नियमों पर पुनर्विचार की वर्तमान मांग को जन्म दिया है। क्रमशः ऑस्ट्रेलिया और क्यूबा के अनुरोध पर, वीटो शक्ति के आवेदन की समीक्षा करने और इसके एकमुश्त उन्मूलन पर विचार करने के प्रस्तावों को संयुक्त राष्ट्र महासभा की अक्टूबर की बैठक के एजेंडे में रखा गया है।

इस बीच, वीटो सिद्धांत के किसी भी संशोधन के सोवियत प्रतिरोध से परमाणु ऊर्जा आयोग का काम बाधित हो रहा है। अन्य महान शक्तियों ने यह मानते हुए कि वीटो के अधिकार का प्रयाग केवल सबसे महत्वपूर्ण कारणों के लिए किया जाना चाहिए, इसके पूर्ण परित्याग पर विचार करने के लिए बहुत कम इच्छा दिखाई है। हालांकि, वे इस बात पर सहमत हैं कि जब तक परमाणु ऊर्जा के नियंत्रण के उपायों को विकसित करने में वीटो को अलग नहीं किया जा सकता है, तब तक इस बात की बहुत कम संभावना है कि मानव जाति को भविष्य के परमाणु युद्ध के डर से मुक्त किया जा सकता है।

संयुक्त राष्ट्र चार्टर लिखने के लिए सैन फ्रांसिस्को में आयोजित सम्मेलन में, वीटो प्रश्न ने दो संघर्षों को जन्म दिया। बिग फाइव और छोटे राष्ट्रों के बीच पहला, अंततः याल्टा फॉर्मूले की व्याख्या को लेकर बिग फाइव के भीतर एक संघर्ष द्वारा छाया हुआ था। जब तक बिग फाइव ने अपने मतभेदों को हल किया था (रूस द्वारा अन्य महान शक्तियों के दृष्टिकोण के साथ उपज के साथ) यह स्पष्ट

International Journal of Research in Social Sciences
Vol. 9 Issue 4, April 2019,
ISSN: 2249-2496 Impact Factor: 7.081
Journal Homepage: http://www.ijmra.us, Email: editorijmie@gmail.com
Double-Blind Peer Reviewed Refereed Open Access International Journal - Included in the International Serial Directories Indexed & Listed at: Ulrich's Periodicals Directory ©, U.S.A., Open J-Gate as well as in Cabell's Directories of Publishing Opportunities, U.S.A

था कि तथाकथित लिटिल 45 अतिरिक्त रियायतें प्राप्त करन की उम्मीद नहीं कर सकता था और उन्होंने अपनी लड़ाई छोड़ दी थी।

छोटे राष्ट्रों ने यह कहते हुए वीटो शक्ति को संशोधित करने के लिए अपना प्रयास शुरू कर दिया कि इसे पैन अमेरिकी प्रणाली जैसी क्षेत्रीय व्यवस्थाओं के तहत प्रवर्तन कार्रवाई में हस्तक्षेप करने के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए।

जिन मामलों में परिषद के सदस्यों (स्थायी सदस्यों सहित) को मतदान से बचना चाहिए, यदि किसी विवाद के पक्ष में मुख्य रूप से उन विवादों के शांतिपूर्ण समाधान से संबंधित निर्णय शामिल हैं जिनकी निरंतरता ष्अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के रखरखाव को खतरे में डाल सकती है।ष इस शीर्ष के तहत परिषद की कार्रवाई में पार्टियों को बातचीत, मध्यस्थता, मध्यस्थता या न्यायिक समाधान जैसे शांतिपूर्ण तरीकों से अपने मतभेदों को सुलझाने के लिए बुलाना शामिल हैय विवाद या स्थिति की जांच के लिए मतदानय उपयुक्त प्रक्रियाओं या समायोजन के तरीकों की सिफारिश करनाय या निपटान की शर्तों की सिफारिश करना। हालांकि एक स्थायी सदस्य, अगर किसी विवाद का कोई पक्ष, परिषद के ऐसे फैसलों पर अपने वीटो का प्रयोग नहीं कर सकता है, तो उसे वोट देने का अधिकार वापस मिल जाता है और अगर कोई विवाद शांति के लिए वास्तविक खतरा बन जाता है या शांति भंग हो जाती है या आक्रामकता का कार्य।

जब सुरक्षा परिषद को ष्शांति के लिए किसी भी खतरे के अस्तित्व का निर्धारण, शांति का उल्लंघन, या आक्रामकता के कार्यष और षसिफारिशें करने, या यह तय करने के लिए कि ख्आर्थिक या सैन्य, , उपाय किए जाएंगे३। अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बनाए रखने या बहाल करने के लिए। " इस प्रकार परिषद का एक स्थायी सदस्य, अगर शांति भंग करने या धमकी देने का दोषी है, तो वह अपने खिलाफ किसी भी दंडात्मक कार्रवाई को वीटो कर सकता है। यह संभावना चार्टर को आत्म–पराजय वाला पहलू देती प्रतीत होती है। लेकिन, यह बताया गया है कि प्रतिबंधों के नाम पर, किसी एक महान शक्ति के खिलाफ सशस्त्र बल लगाना युद्ध के बराबर होगा। यदि अन्य महान शक्तियाँ ऐसे मामले में सशस्त्र प्रतिबंधों को लागू करने के लिए तैयार होतीं, तो निस्संदेह स्थिति पहले से ही बिगड़ गई होती, जहाँ आपत्तिजनक पार्टी द्वारा वीटो के अधिकार से कोई फर्क नहीं पड़ता। जहां तक आर्थिक प्रतिबंधों का सवाल है, वे आसानी से सशस्त्र हस्तक्षेप के अग्रदूत हो सकते हैं।

हालाँकि, वीटो शक्ति को चार्टर में शामिल नहीं किया गया था ताकि सुरक्षा परिषद के एक स्थायी सदस्य को अपने खिलाफ प्रवर्तन कार्रवाई को रोकने में सक्षम बनाया जा सके। इसका समावेश

International Journal of Research in Social Sciences
Vol. 9 Issue 4, April 2019,
ISSN: 2249-2496 Impact Factor: 7.081
Journal Homepage: http://www.ijmra.us, Email: editorijmie@gmail.com
Double-Blind Peer Reviewed Refereed Open Access International Journal - Included in the International Serial Directories Indexed & Listed at: Ulrich's Periodicals Directory ©, U.S.A., Open J-Gate as well as in Cabell's Directories of Publishing Opportunities, U.S.A

राजनीतिक वास्तविकताओं और सामान्य विचारों से प्रेरित था। जैसा कि बिग फाइव ने 8 जून, 1945 के अपने बयान में कहा थारू ष्स्थायी सदस्यों की प्राथमिक जिम्मेदारियों को देखते हुए, उनसे उम्मीद नहीं की जा सकती थी कि दुनिया की वर्तमान स्थिति में, वे इतने गंभीर रूप से कार्य करने के दायित्व को मानेंगे।ष एक निर्णय के परिणामस्वरूप अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के रखरखाव के रूप में मामला जिस पर उन्होंने सहमति नहीं दी थी।ष

चार्टर, वास्तव में, महान शक्तियों को छोटे राज्यों के बीच युद्धों को रोकने या रोकने के लिए मशीनरी से लैस करता था लेकिन उनके बीच युद्धों को रोकने के लिए केवल सीमित साधन प्रदान करता था। क्या वीटो शक्ति को हटाने से बाद की स्थिति बदल जाती, यह संदिग्ध है। किसी भी मामले में, यह एक व्यावहारिक संभावना नहीं थी। और यह माना जा सकता है कि वीटो के अधिकार ने महान शक्तियों के बीच संघर्ष की संभावना को कम कर दिया, सुरक्षा परिषद ने उनमें से किसी एक को मजबूर करने का प्रयास किया। इस नकारात्मक अर्थ में वीटो शक्ति को अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देने वाला माना जा सकता है। लेकिन यह उम्मीद नहीं की जा सकती है कि अगर वीटो रखने वाले राज्य अंतरराष्ट्रीय समुदाय के हितों के लिए उचित सम्मान के बिना राष्ट्रीय हितों की खोज में इसका इस्तेमाल करते हैं तो इसका परिणाम होगा।

हालांकि वीटो शक्ति सामान्य रूप से प्रक्रियात्मक प्रश्नों पर लागू नहीं होती है, बिग फाइव ने सैन फ्रांसिस्को में यह स्पष्ट कर दिया कि वे उन निर्णयों को नियंत्रित करने का अधिकार सुरक्षित रखते हैं जो प्रक्रियात्मक या मूल थे। इसने उन्हें एक प्रकार की दोहरी वीटो शक्ति प्रदान की। यह छोटे राष्ट्रों की स्थिति रही है, और मूल रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका और ब्रिटेन की भी, ऐसे प्रश्नों का निर्धारण एक प्रक्रियात्मक मत द्वारा शासित होना चाहिए।

8 जून, 1945 के अपने व्याख्यात्मक बयान में, बिग फाइव ने कहा कि उन्हें लगा कि यह संभव नहीं है कि ष्कोई भी महत्वपूर्ण मामलाष सामने आएगा, जिस पर निर्णय लेना होगा। ष्हालांकि, अगर ऐसा कोई मामला उठता है, तो इस तरह के मामले के प्रक्रियात्मक होने या न होने के प्रारंभिक प्रश्न के बारे में निर्णय सुरक्षा परिषद के सात सदस्यों के वोट से लिया जाना चाहिए, जिसमें स्थायी सदस्यों के सहमति वाले वोट भी शामिल हैं।ष इस प्रथा का पालन आज तक किया जाता रहा है, लेकिन कुछ छोटे राष्ट्रों के विरोध के बिना नहीं। इस विषय पर विशेषज्ञों की एक समिति द्वारा विचार किया जा रहा है, जो कथित तौर पर बिग फाइव व्याख्या के पालन पर रूस के आग्रह के कारण एक समझौते पर पहुंचने में असमर्थ रहे हैं।

International Journal of Research in Social Sciences
Vol. 9 Issue 4, April 2019,
ISSN: 2249-2496 Impact Factor: 7.081
Journal Homepage: http://www.ijmra.us, Email: editorijmie@gmail.com
Double-Blind Peer Reviewed Refereed Open Access International Journal - Included in the International Serial Directories Indexed & Listed at: Ulrich's Periodicals Directory ©, U.S.A., Open J-Gate as well as in Cabell's Directories of Publishing Opportunities, U.S.A

निष्कर्ष

जब सुरक्षा परिषद ने परमाणु ऊर्जा आयोग के लिए प्रक्रिया के नियमों की चर्चा में भाग लेने के लिए कनाडा को आमंत्रित करने के लिए 10 जुलाई को मतदान किया, तो सोवियत प्रतिनिधि ने तर्क दिया कि उनके नकारात्मक वोट ने वीटो का गठन किया। हालांकि, वह सभापति के निर्णय को रद्द करने के प्रस्ताव पर मतदान के लिए जोर देने में विफल रहे कि प्रश्न प्रक्रियात्मक था, और इसलिए कनाडा के प्रतिनिधि को भर्ती किया गया। ब्रिटिश प्रतिनिधि ने बताया कि संयुक्त राष्ट्र के अन्य सदस्यों को विशेष रूप से उनके हितों को प्रभावित करने वाले मामलों की सुरक्षा परिषद की चर्चा में बैठने के लिए निमंत्रण प्रदान करने वाले चार्टर के लेख को ष्प्रक्रियाष् नामक एक खंड के तहत शामिल किया गया था। ऑस्ट्रेलिया के इवाट ने यह भी बताया कि बिग फाइव ने विशेष रूप से घोषित किया था कि इस तरह के निमंत्रण एक प्रक्रियात्मक मत द्वारा शासित होंगे।

संदर्भ

- सिंह, जसजीत, भारतीय परमाणु शस्त्र (एक नई दि"ाा) प्रभात प्रका"ान, 2019.
- शर्मा, अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध, पंच"ाील प्रका"ान, जयपुर।
- शर्मा, मथुरा लाल : अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध, कालेज बुक डिपो, नई दिल्ली 2018
- नायक, बलदेव राज : अमेरिका और भारत संघर्ष की जड़ें।
- बाला मनमोहन, रक्षा विज्ञान, प्रभात प्रका"ान, नई दिल्ली–2020. 148
- सिंह, लल्लन जी : राष्ट्रीय सुरक्षा और प्रतिरक्षा प्रका"ा बुक डिपो, बरेली, 2015.
- पन्त, पुष्पे"ा : अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति, मिनाक्षी प्रका"ान, मेरठ, 2014.
- राय, गाँधी जी : अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति, भारतीय भवन, पटना–2018.
- पन्त, पुष्पे"ा : अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध, मीनाक्षी प्रका"ान, मेरठ, 2018.
- दीक्षित, जे0एन0 : भारतीय विदे"ा नीति, प्रभाव पका"ान, नई दिल्ली, 2019.